ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अभाव के कारण

डॉ0 दिनेश प्रसाद मिश्र
एसो0 प्रोफेसर शिक्षा संकाय
कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान,
सुल्तानपुर (उ0प्र0)

सारांशिका

वैज्ञानिक विकास एवं भौतिक उपलब्धियों की धुन से जूझता हुआ आज का मनुष्य जहॉ अनेक संत्रासों से घायल है। उसकी मन की संकीर्णता और आस्वादन की चाह उसे चारो ओर बाँधे हुये है। ऐसे में मनुष्य को सुख शान्ति की गली में ले जाने वाला लोकगीत ही उसका अवलम्ब हो सकता है। राष्ट्र की आत्मा गाँव में ही बसती है, इसलिए गाँवों का विकास किये बिना राष्ट्र का विकास करना कपोलकल्पित कल्पना मात्र है । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस तथ्य की स्वीकारोक्ति कुछ इन शब्दों में की है– ''यदि हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो इसकी शुरूआत गाँव से ही करनी होगी ।''

मुख्य शब्दः पंख, सीपियां, मंगल, भावना, भ्रमर गीत

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा और ज्ञान के बिना सही मायने में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती । शिक्षा ही वह मशाल है, जिसके द्वारा अज्ञानता के तीव्रतम् तिमिर को भेदकर मानव और मानवता दोनों का उद्धार किया जा सकता है । शिक्षा ही वह साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है और वह अपने व्यक्तित्व में समाहित गुणों के माध्यम से समाज और राष्ट्र को उन्नतिशील बनाता है । सूचना समृद्धि के इस दौर में शिक्षा का विशेष महत्व है । समावेशी और चतुर्दिक आर्थिक व सामाजिक विकास का स्वप्न तभी मूर्तवत् होगा, जब देश के सभी जन शिक्षित होंगे । भारत सरीखे विकासशील राष्ट्र जो अज्ञानता, गरीबी, गन्दगी और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से निरन्तर संघर्षशील है, के लिए शिक्षा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है । भारत आज भी नगरीकरण से दूर अपनी समस्याओं से उलझता, घिसटता ग्रामीण भारत की संज्ञा से सुशोभित है। देश की अधिकांश जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 69 प्रतिशत गाँवों में निवास करती है । भारत में कुल 6.41 लाख गाँव हैं अर्थात् भारत मूलतः गाँवों का देश है । राष्ट्र की आत्मा गाँव में ही बसती है, इसलिए गाँवों का विकास किये बिना राष्ट्र का विकास करना कपोलकल्पित कल्पना मात्र है । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस तथ्य की स्वीकारोक्ति कुछ इन शब्दों में की है– ''यदि हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो इसकी शुरूआत गाँव से ही करनी होगी ।''

प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य जाहिर करता है कि सरकार की सोच गाँव की शिक्षा और विकास को लेकर क्या है ? स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों उपरान्त भी हमारे गाँव आज भी मूलभूत सुविधाओं से हीन विकास की राह देख रहे हैं । अशिक्षा से अभिशप्त इन गाँवों की अधिकांश जनसंख्या आज भी दयनीय और पिछड़ा जीवन जीने के लिए बाध्य है । अधिकांश ग्रामीण लोगों में शिक्षा विषय को लेकर कोई जागरूकता नहीं है । तकनीकी विकास के क्षेत्र में जहाँ देश नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं गाँव के लोग शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण कठोर श्रमसाध्य जीवन व्यतीत करने के लिए विवश है । उदर पूर्ति को ही अपना जीवन लक्ष्य मानकर शोषण और गरीबी का शिकार हो रहे हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव देश की सम्पूर्ण आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ रहा है । अनेक यत्न–प्रयत्न के बाद भी राष्ट्र निर्धनता के दुश्चक्र को तोड़ नहीं पा रहा है । निरक्षरता या अशिक्षा भारतीय सभ्यता के सम्मुख एक चुनौती के रूप में खड़ी है, जिससे निपटे बिना समावेशी विकास के संवैधानिक दर्शन को पूरा नहीं किया जा सकता । प्रस्तुत अध्ययन इसी संदर्भ में एक लघु यत्न के रूप में है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षिक समस्याओं की तथ्यात्मक व वास्तविक स्थिति को उजागर किया जा सके ।

समस्या का उद्भव एवं स्वरूप :

भारत अभी भी गाँवों का महासागर है । देश की लगभग दो तिहाई आबादी गाँवों में निवास करती है । गाँवों की महत्ता का पता गाँधी जी के इस वक्तव्य से भी मिलता है कि– ''भारत की आत्मा गाँवों में बसती है'' यूँ तो आजादी के बाद से ही गाँव भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों की नीतियों के केन्द्र में रहा है, किन्तु अभी भी ग्रामीण ढाँचे में आशानुरूप परिवर्तन दृष्टिगोचित नहीं होते बात चाहे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं की हो अथवा शिक्षा, कौशल विकास जैसी सामाजिक सेवाओं की आज भी ग्रामीण भारत असल में भारतीय शहरों के मुकाबले कमतर नजर आता है । दरअसल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस गहनता और व्यापकता से ग्रामोत्थान के लिए प्रयास किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया, जिसका दुष्परिणाम आज कहीं न कहीं सम्पूर्ण राष्ट्र भुगत रहा है । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने लिखा है कि– ''भारत समय से अपनी प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में पर्याप्त निवेश न करने की कीमत भुगत रहा है ।'' वास्तव में शिक्षा किसी भी समाज के प्रगति की नींव होती है और इसमें भी प्राथमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है । 21वीं शदी का भारत कालचक्र के ऐसे रोचक मोड़ पर खड़ा है, जहाँ वह अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विस्मयकारी उपलब्धि अर्जित कर रहा है, तो दूसरी ओर देश में कुछ ऐसे समुदाय हैं, जो निरक्षरता के आवरण में लिपटे हुए मानों आदिम युग में जीने के लिए विवश हैं। निरक्षरता व अशिक्षा अभी भी आधुनिक भारतीय समाज के समक्ष

चुनौती प्रस्तुत कर रही है । यू0एन0डी0पी0 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 3 करोड़, 50 लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं, जिसमें दो तिहाई लड़कियाँ हैं । पूरे विश्व में कुल जितने निरक्षर हैं, उनमें आधे भारत में ही हैं । भारत में 35% प्रौढ़ अभी भी निरक्षर हैं । जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74-04% है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 82-14% तथा स्त्री साक्षरता दर 65-46% है। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 84-98% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 68-91% है । ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है जहाँ ग्रामीण पुरूष साक्षरता 95-29% है तथा ग्रामीण महिला साक्षरता 90-74% है जबकि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला राज्य अरूणांचल प्रदेश है जहाँ 4

ग्रामीण पुरूषों की साक्षरता दर 68.79% है और ग्रामीण महिला साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा राज्य राजस्थान है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर 46.25% है। जनगणना 2011 से प्राप्त शैक्षिक आंकड़ों को 2001 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से तुलना कर ग्रामीण और शहरों की शैक्षिक प्रगति का तुलनात्मक वर्णन अधोलिखित सारिणी के माध्यम से किया जा सकता है– महिला व पुरूष साक्षरता दर प्रतिशत में

वर्ष		पुरूष साक्षरता दर		महिला साक्षरता दर	
भारत	ग्रामीण	शहरी	भारत	ग्रामीण	शहरी
2001	75.3 82.1	70.07 78.6	86.3 89.7	53.7 65.5	46.1 58.8	72.9 79.9
2011						
अन्तर	+6.8	+7.9	+3.4	+11.8	+12.7	+7

जनगणना 2011 के अनुसार

उपरोक्त सारिणी का यदि अवलोकन किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि गाँवों की शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ है, किन्तु अभी भी स्थिति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला–पुरूष की साक्षरता दर का अन्तर जिसे लैंगिक साक्षरता दर कहा जाता है, का मान काफी उच्च लगभग 16-6% है जिससे स्पष्टतया प्रदर्शित होता है कि ग्रामींण महिलायें भारी मात्रा में अभी भी अशिक्षित हैं । इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि साक्षरता को लेकर देश में समान स्थिति नहीं है । शहरों 5 की अपेक्षा गाँव और पुरूषों की तुलना में महिलायें अधिक निरक्षर हैं, जिसे किसी भी रूप में देश के लिए हितकर नहीं कहा जा सकता है ।

समस्या उद्भव के कारण : भारत में जनगणना आयोग 1991 के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति जो किसी भी भारतीय भाषा को समझ के साथ लिख और पढ़ सकते हैं, साक्षर कहलाते हैं। भारत में निरक्षरता की तस्वीर बड़ी भयावह है, जिसके लिए वस्तुतः कई तत्व उत्तरदायी हैं । इन तत्वों का अध्ययन अशिक्षा के कारण के रूप में इस प्रकार से किया जा सकता है ।

1. आर्थिक कारण : ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का व्यापक संचार देखने को मिलता है लगभग 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को मजबूर हैं । अधिकांश ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं होती है अर्थाभाव से ग्रस्त बहुत से अभिभावक अपने बच्चों पर होने वाले साक्षरता व्यय को वहन करने में अक्षम होते हैं । आर्थिक तंगी बच्चों को बालश्रम करने पर विवश कर देती है । अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी भी लगभग 1 करोड़ 26 लाख बच्चे बालश्रम करने को मजबूर हैं । यदि बच्चा येन–केन प्रकारेण स्कूल में प्रवेश ले भी लेता है तो वह स्कूल बीच में ही छोड़ देता है । लगभग 40% है बच्चे 5वीं तक तथा 55% बच्चे 8वीं तक की शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते ।

2. सामाजिक कारण : ग्रामीण अशिक्षा के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारणों में लिंग भेद एक प्रमुख कारण है, जिससे प्राथमिक शिक्षा में केवल 44 % लड़कियाँ ही नामांकित हो पाती हैं । पुरूष प्रधान मानसिकता, पर्दाप्रथा, बालविवाह, रूढ़िवादिता, पुरातनपंथी सोच, आधी आबादी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार आदि ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा को बढ़ावा देते हैं । प्राथमिक स्कूलों की दूरी एवं इनमें महिला शिक्षिकाओं का अभाव, बालिका शिक्षा के संदर्भ में मंदक का कार्य करते हैं, भारत में अभी भी मात्र 40% महिला शिक्षिकायें हैं। प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों की अनुपयुक्त व्यवस्था, अधिक शिक्षा अधिक दहेज की मान्यता, छोटे बच्चों की देख–रेख, बालिका शिक्षा के मार्ग में कंटक बन ग्रामीण अशिक्षा दर में वृद्धि कर रही हैं । भारत के पिछड़े जिलों में स्थिति इतनी खराब है कि लगभग 90% महिलायें निरक्षर हैं ।

3. राजनैतिक कारण : ग्रामीण अंचलों में अशिक्षा के लिए राजनैतिक कारण भी कम उत्तरदायी नहीं हैं । शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने में 28 वर्ष लग गये । पाठ्य सामग्री का अभाव एवं अध्यापकों की कमी के पीछे राजनैतिक–प्रशासनिक उपेक्षा का भी हाथ है । सुदूर बस्तियों तक सरकारी नीतियों की पहुँच का अभाव है । बहुत सी शिक्षण संस्थायें मात्र कागजों पर कार्यरत हैं यथार्थ में उनकी स्थापना ही नहीं हुई है। भारत में 20% से अधिक स्कूल बिना श्यामपट्ट के चल रहे हैं । 80% प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षण कक्ष नहीं हैं । 45% प्राथमिक विद्यालयों में बैठने की टाटपट्टी तक नहीं है । एक तिहाई विद्यालय मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं । निर्देशन, परामर्श, मूल्यांकन आदि सेवाओं का सरकारी विद्यालयों में पूर्णतया अभाव है। शिक्षकों से समय–समय पर शिक्षण कार्य से इतर बहुत से कार्य करवाये जाते हैं, जिससे गुणात्मक शिक्षा का माहौल खराब होता है ।

4. जनांककीय कारण : जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है । सुरसा के मुँह की तरह जनसंख्या का आकार निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है । शहरों की तुलना में गाँव जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से अधिक उर्वर साबित हो रहे हैं । बहुत से ग्रामीण अभिभावकों के जेहन में यह बातघर कर जाती है कि ज्यादा हांथ, ज्यादा कमाई । अतः वे गरीबी दूर करने के लिए जनसंख्या के नियंत्रण के लाभ व तरीकों से बेखबर संतानोत्पत्ति में संलग्न रहते हैं। फलतः जनसंख्या विस्फोट के कारण देश को शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

5. भौगोलिक कारण : भारत विश्व का 7वाँ सबसे बड़ा देश है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2-4% हिस्सा भारत का है, जो प्राकृतिक विविधताओं से भरा हुआ है । एक तरफ समतल उपजाऊ मैदान है तो दूसरी तरफ नदी, पहाड़, जंगल जैसे दुर्गम क्षेत्र भी हैं,

जहां अनेक जनजातियाँ विशाल समूहों में निवास करती हैं । इन दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक पिछड़ापन मौजूद है । दुर्गम मार्ग और सुदूर स्थित शिक्षण संस्थाओं तक बच्चों की पहुँच अभी तक नहीं हो पा रही है । गर्मी, सर्दी, वर्षा, तूफान, भूकम्प आदि के कारण भी शिक्षण कार्य आये दिन बाधित रहता है । फलस्वरूप इन पिछड़े क्षेत्रों में अभी शिक्षा का आलोक पूरी तरह फैल नहीं सका है जिससे सकल ग्रामीण निरक्षरता दर में वृद्धि हो रही है ।

निष्कर्षः– वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के युग में निरक्षरता मानव जीवन के लिए अभिशाप तुल्य है । यह आधुनिक होने का दम्भ भरने वाले समाज के माथे पर कलंक के समान है । पूर्व राष्ट्रपति ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम के अनुसार–''राष्ट्र के विकास व समृद्धि के लिए सबसे जरूरी तत्व शिक्षा है ।'' वस्तुतः सम्मान के लिए शिक्षा जरूरी है किन्तु निरक्षरता के रहते शिक्षा कैसे सम्भव है ? मदन मोहन मालवीय जी ने शिक्षा को समस्त सुधारों की जड़ माना है । सामान्य जन के कल्याण, सुखी जीवन, राष्ट्रीय एकता एवं देश की आर्थिक समृद्धि हेतु शिक्षा आवश्यक है । ''सब पढ़ें–सब बढ़ें'' का ध्येय पूरा करने के लिए जरूरी है कि शहर, गाँव सभी जगह शिक्षा की ज्योति जलाई जाय जिससे राष्ट्र का समतामूलक, समदर्शी और समावेशी विकास सम्भव हो सके ।

सन्दर्भ सूची

1. श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था।
   संकान्तिरन्यस्य विशेशयुक्ता।
   यस्योभवं साधु स शिक्षकाणां
   धुरि प्रति ठापयितव्य एवं।। कालिदास मालविकाग्निमित्र, 1–16
2. हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल पृ0 – 61
3. हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल पृ0 – 146
4. रवीन्द्रनाथ ठाकुर कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1932 का भाशण
5. खलील जिब्रानन जीवन–सन्देश, पृ0 – 67
6. ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, आर0 लाल बुक डिपो, एन0आर0 स्वरूप सक्सेना, डॉ0 डी0पी0 मिश्र, पृ0 438–439
7. https://m.jagaran.com/new Thus. 19 Oct 2017